आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार एकांश
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शुक्रवार 21.02.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- उत्तराखंड विधानसभा के चौथे दिन की कार्यवाही आज पूर्वाह्न ग्यारह बजे शुरू होगी, शनिवार को भी चलेगी सदन की कार्यवाही।
- अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने यू०सी०सी पोर्टल पर वैवाहिक और अन्य पंजीकरणों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर समान नागरिक संहिता को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। लिव–इन संबंधों के अनिवार्य पंजीकरण पर कहा– यह प्रावधान युगलों की सुरक्षा के लिए है।
- राज्यपाल ने किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिये न्यूनतम निवेश वाली कृषि उद्यम योजनाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

विधानसभा कार्यवाही

उत्तराखंड विधानसभा के चौथे दिन की कार्यवाही आज पूर्वाह्न ग्यारह बजे से शुरू होगी। विधानसभा सत्र को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया है। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में पहली बार शनिवार को भी सदन की कार्यवाही चलाने का फैसला किया गया।

उत्तराखंड विधानसभा में भूमिधरी के मुद्दे को लेकर नियम 58 के तहत चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर समाधान में लापरवाही का आरोप लगाया। धारचूला के विधायक हरीश धामी ने सीमांत क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि वहां के लोग अपनी ही जमीन पर भूमिहीन बने हुए हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि हर बार सदन में यह मुद्दा उठाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। हालांकि, वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इस पर जवाब दिया, लेकिन इससे कांग्रेस विधायक असंतुष्ट नजर आए। जवाब से नाराज होकर कांग्रेस विधायकों ने सदन के वेल में आकर नारेबाजी की और फिर वाकआउट कर दिया।

बजट

इससे पहले, कल दोपहर में उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए लगभग एक लाख एक हजार एक सौ पचहत्तर करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में तेरह प्रतिशत अधिक है। इस बजट में दो हजार पांच सौ पचासी करोड़ रुपये के राजस्व अधिशेष और लगभग बारह हजार छह सौ पांच करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे का अनुमान है, जो राज्य की वित्तीय सीमाओं के भीतर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे प्रदेश की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं का खाका बताते हुए कहा कि यह इकोलॉजी, इकोनॉमी, सस्टेनेबल और समावेशी विकास पर केंद्रित है।

सख्त भू–कानून

उत्तराखंड में भूमि की आवश्यकता से ज्यादा खरीद–फरोख्त पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य विधानसभा में उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) संशोधन विधेयक पेश किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए यह सख्त भूमि विधेयक पेश किया गया है। यह राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने और जनता के हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

यू०सी०सी पोर्टल प्रगति समीक्षा

अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने समान नागरिक संहिता–यू०सी०सी पोर्टल की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पोर्टल पर वैवाहिक और अन्य पंजीकरणों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही, सभी शासकीय कार्मिकों के लिए वैवाहिक पंजीकरण अनिवार्य करने के लिये विशेष अभियान चलाने को कहा। उन्होंने शिक्षा और पुलिस विभागों को पंजीकरण लक्ष्य निर्धारित करने और अभियोजन अधिकारियों को यूसीसी के प्रचार–प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए।

श्री बर्द्धन ने यू०सी०सी जागरूकता के लिये कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए, जिसमें जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और नोडल अधिकारी भाग लेंगे। उन्होंने आईटीडीए को यूसीसी पोर्टल के तकनीकी मुद्दों को शीघ्र सुलझाने और डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देने को कहा।

आरोप

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान में विश्वास नहीं रखती और महिलाओं पर अत्याचार करने वालों का समर्थन करती है।

लिव–इन संबंधों के अनिवार्य पंजीकरण प्रावधान पर कांग्रेस के विरोध को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान युगलों की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में लिव–इन संबंधों में विवाद उत्पन्न होने पर हिंसक घटनाएं बढ़ती हैं।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के इस बयान को भी खंडित किया जिसमें कहा जा रहा था कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड की लड़की से शादी करता है, तो उसे मूल निवासी का दर्जा मिल जाएगा। उन्होंने इसे पूरी तरह निराधार और भ्रामक करार दिया।

कृषि विज्ञान सम्मेलन–राज्यपाल संबोधन

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिये न्यूनतम निवेश वाली कृषि उद्यम योजनाओं जैसे मधुमक्खी पालन और मशरूम की खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन को संबोधित करते हुये राज्यपाल ने कहा कि कृषि अनुसंधान को किसानों तक सीधे पहुंचाने के लिए 'लैब टू लैंड' और 'लैब टू पीपल' कार्यक्रमों को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के लाभों को भी रेखांकित किया और कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और डिजिटल तकनीकों के महत्व पर जोर दिया। गौरतलब है कि इस तीन दिवसीय कृषि विज्ञान सम्मेलन में तीन हजार से अधिक नीति निर्माता, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, किसान और उद्योग प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस वर्ष का विषय "विकासशील भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी" है, जिसमें कृषि में नवीन तकनीकों की भूमिका पर चर्चा हो रही है।

मौसम

प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल हुई बर्फबारी और निचले इलाकों में रुक–रुक कर हुई बारिश से ठंड लौट आई है। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री, यमुनोत्री मंदिर और हर्षिल सहित अन्य हिस्सों में बर्फबारी हुई। इसके अलावा बदरीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, फूलों की घाटी, चोपता और औली में भी ताजा बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटक खासे उत्साहित दिखे। इस बीच, मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज मौसम साफ बने रहने का अनुमान जताया है। हालांकि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के अत्यधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में कहीं–कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है।

एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर———

उत्तराखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025—26 के लिये पेश बजट की ख़बर सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। दैनिक जागरण लिखता है— विकसित उत्तराखंड का सशक्त संकल्प, एक लाख एक हजार एक सौ पचहत्तर दशमलव तीन—तीन करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। विकास के साथ सामाजिक सुरक्षा को संबल दे रही बजट पोटली। इसी ख़बर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र का शीर्षक है— पहली बार, एक लाख करोड़ पार... धामी सरकार के नमो बजट में नवाचार, आत्मनिर्भरता, महान विरासत और ओजस्विता की भावना। उत्तराखंड में डॉक्टरों के खाली पद तीन साल में भरे जाएंगे। विधानसभ में हुई कार्यवाही के हवाले से राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र लिखता है— स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह ने सदन में प्रश्नों के जवाब में दी जानकारी।

कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये छह किलोमीटर लंबी टनल बनाई जाएगी। अमर उजाला समाचार पत्र के अनुसार बूंदी से गर्ब्यांग तक सुरंग बनने से दस किलोमीटर की दूरी कम होगी।

प्रदेश के ऊंचाई वाले स्थानों और हिल स्टेशनों में बर्फबारी की ख़बर पर राष्ट्रीय सहारा सचित्र लिखता है— चकराता, धनोल्टी, बुरांसखंडा सुरकंडा की चोटियों में बर्फबारी, हिमपात से किसानों व बागान मालिकों के चेहरे खिले।

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर—

- उत्तराखंड विधानसभा के चौथे दिन की कार्यवाही आज पूर्वाह्न ग्यारह बजे शुरू होगी, शनिवार को भी चलेगी सदन की कार्यवाही।
- अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने यू०सी०सी पोर्टल पर वैवाहिक और अन्य पंजीकरणों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर समान नागरिक संहिता को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। लिव—इन संबंधों के अनिवार्य पंजीकरण पर कहा— यह प्रावधान युगलों की सुरक्षा के लिए है।
- राज्यपाल ने किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिये न्यूनतम निवेश वाली कृषि उद्यम योजनाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया।